भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2535

(04 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

सरस मेला

2535. श्री तंगेला उदय श्रीनिवास:

श्री जी. लक्ष्मीनारायण:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ई-सरस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत महिला स्व-सहायता समूहों (एसएचजी), किसान उत्पादक संगठनों (एफ़पीओ) और आंध्र प्रदेश के लिए जिला-वार ब्यौरे सहित अन्य ग्रामीण उद्यमों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) ई-सरस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए गए बिक्री का मूल्य और मात्रा कितनी है जिसे आंध्र प्रदेश सहित राज्य और जिला-वार वर्गीकृत किया गया है;

(ग) देश में आयोजित किए गए सरस मेलों की संख्या कितनी है और इसमें भाग लेने वाले एसएचजी/एफपीओ, दर्शकों की संख्या, उत्पन्न बिक्री और ऐसे मेलों में भाग लेने वाले प्रमुख संस्थागत और खुदरा खरीदारों की राज्य और जिला-वार संख्या क्या है;

(घ) प्रशिक्षण, डिजिटल क्षमता निर्माण, विपणन सहायता और संभार तंत्र सहायता सहित अधिक एसएचजी, एफपीओ और ग्रामीण उत्पादकों के ई-सरस प्लेटफॉर्म पर जोड़ने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं; और

(ड.) क्या सरकार ने ग्रामीण उत्पादकों की बाजार तक पहुंच और आय बढ़ाने पर ई-सरस प्लेटफॉर्म और सरस मेलों के प्रभाव का कोई आकलन किया है और यदि हॉ, तो इसके प्रमुख निष्कर्षों और परिणामों से संबंधित ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क) और (ख) मंत्रालय ने ई-सरस प्लेटफॉर्म विकसित और लॉन्च किया है, जो एसएचजी उत्पादों के लिए एक विशिष्ट डिजिटल बाजार के रूप में कार्य करता है। अपने स्वयं के प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रत्यक्ष बिक्री की सुविधा के अलावा, ई-सरस अन्य प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर एसएचजी उत्पादों के ऑनबोर्डिंग और बिक्री को भी सक्षम बनाता है।

अन्य प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म (फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मीशो आदि) सहित ई-सरस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत एसएचजी/एफपीओ आदि, बिक्री का मूल्य और मात्रा का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

(ग) मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अपने संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रतिवर्ष कम से कम दो सरस मेलों का आयोजन कर सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में, चार राष्ट्रीय स्तर के मेलों का आयोजन किया गया है, जिनकी कुल बिक्री 35.73 करोड़ रुपये हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार अनुसार विवरण अनुबंध II में दिए गए हैं।

(घ) ई-सरस प्लेटफॉर्म एक डिजिटल बाज़ार है जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के सहयोग से विकसित किया है, ताकि महिला-नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), ग्रामीण कारीगरों और उत्पादक समूहों को अपने उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर विपणन करने में सक्षम बनाया जा सके। अधिक एसएचजी, एफपीओ, ग्रामीण उत्पादकों को ऑनबोर्ड करने और उनकी बाजार पहुंच को सुदृढ़ करने के लिए, मंत्रालय ने ऑनलाइन उत्पाद कैटलॉग, इन्वेंट्री प्रबंधन और सुरक्षित डिजिटल भुगतान सुविधाओं सहित डिजिटल ऑनबोर्डिंग सहायता प्रदान की है। एसएचजी से जुड़ी महिलाओं को डिजिटल ऑनबोर्डिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, उत्पाद फोटोग्राफी, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राहक सेवा और उत्पाद मूल्य निर्धारण में प्रशिक्षण दिया जाता है। एसएचजी उत्पादों के उत्पाद संग्रह, पैकेजिंग, इन्वेंट्री प्रबंधन और अंतिम छोर तक प्रदायगी को सुव्यवस्थित करने के लिए एक समर्पित पूर्ति केंद्र स्थापित किया गया है। क्षमता निर्माण पहल निर्यात के लिए तैयार एसएचजी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल मार्केटिंग और चयनित व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी की सुविधा पर केंद्रित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान नियमित रूप से उत्पाद विकास, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, गुणवत्ता सुधार, डिजिटल विपणन, उद्यम प्रबंधन, निर्यात प्रक्रियाओं और प्रलेखन, तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक उनकी पहुंच को सुदृढ़ करने के लिए बाजार तत्परता पर एसएचजी सदस्यों को सहायता प्रदान करने के लिए क्षमता निर्माण और कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करता है।

(ङ) मंत्रालय नियमित रूप से बिक्री रिपोर्ट और आवधिक रूप से राज्यों के साथ परामर्श के माध्यम से ई-सरस प्लेटफॉर्म और विपणन पहलों, जिनमें सरस मेलें भी शामिल है, के

निष्पादन की समीक्षा करता है। आकलन में पाया गया है कि इन पहलों ने महिलाओं के एसएचजी को उनके स्थानीय बाजारों से परे ग्राहकों के साथ वास्तविक और डिजिटल दोनों चैनलों के माध्यम से जोड़कर बाजार पहुंच में काफी वृद्धि की है। सरस मेलों ने एसएचजी को प्रत्यक्ष विपणन अवसर प्रदान किए हैं, उत्पाद दृश्यता में वृद्धि की है, संस्थागत और खुदरा खरीदारों के साथ बातचीत को सुगम बनाया है, और पर्याप्त उत्पाद की बिक्री की है, जबकि ई-सरस ने साल भर ऑनलाइन बाजार पहुंच को सक्षम किया है।

****

अनुबंध-I

अन्य प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म (फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मीशो आदि) सहित ई-सरस प्लेटफार्म पर पंजीकृत एसएचजी/एफपीओ आदि, बिक्री का मूल्य और मात्रा, का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**एसएचजी/एफपीओ की संख्या**	**बिक्री का मूल्य (₹)**	**मात्रा (यूनिट)**
1.	आंध्र प्रदेश	5	1,07,583	51
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	0	0
3.	असम	9	19,252	59
4.	बिहार	5	44,605	53
5.	छत्तीसगढ़	5	54,497	37
6.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	1	190	1
7.	गोवा	3	2,369	5
8.	गुजरात	5	984	2
9.	हरियाणा	11	4,04,003	979
10.	हिमाचल प्रदेश	6	54,324	137
11.	जम्मू और कश्मीर	7	5,42,537	1,142
12.	झारखंड	15	2,29,713	591
13.	कर्नाटक	11	3,35,667	630
14.	केरल	4	17,437	67
15.	मध्य प्रदेश	11	6,52,534	1,325
16.	महाराष्ट्र	11	19,151	50
17.	मणिपुर	1	0	0
18.	मेघालय	3	9,017	13
19.	मिज़ोरम	1	0	0
20.	ओडिशा	22	2,13,206	207
21.	पुदुचेरी	1	1,960	12
22.	पंजाब	16	3,40,305	706
23.	राजस्थान	14	2,99,373	629
24.	तेलंगाना	1	0	0
25.	त्रिपुरा	4	15,534	46
26.	उत्तर प्रदेश	44	1,07,03,611	34,766
27.	उत्तराखंड	10	14,791	31
28.	पश्चिम बंगाल	22	2,00,272	430
कुल		249	1,42,82,915 **(₹ 1.43 करोड़ में)**	41,969

अनुबंध- II

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान दिल्ली एनसीआर में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के सरस मेलों का विवरण।

क्र.सं.	राज्य का नाम	कुल बिक्री (₹)	भागीदार सदस्यों की संख्या (एसएचजी/एफपीओ/आदि)
1	आंध्र प्रदेश	13035245	75
2	अरुणाचल प्रदेश	2022188	39
3	असम	9446590	53
4	बिहार	15530833	86
5	छत्तीसगढ़	8462799	66
6	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	102700	2
7	गोवा	6194471	34
8	गुजरात	15888588	77
9	हरियाणा	15934414	62
10	हिमाचल प्रदेश	10472682	78
11	जम्मू और कश्मीर	13432510	67
12	झारखंड	9600265	74
13	कर्नाटक	6690107	55
14	केरल	14354902	75
15	लद्दाख	2551291	20
16	मध्य प्रदेश	8014177	64
17	महाराष्ट्र	12203720	74
18	मणिपुर	1861930	14
19	मेघालय	902343	19
20	मिज़ोरम	869095	12
21	नागालैंड	1830240	25
22	ओडिशा	10802780	64
23	पुदुचेरी	2212638	14
24	पंजाब	11560465	61
25	राजस्थान	26345062	100
26	सिक्किम	2296225	29
27	तमिलनाडु	9702575	79
28	तेलंगाना	13649350	69

29	त्रिपुरा	3455115	23
30	उत्तर प्रदेश	32534602	127
31	उत्तराखंड	17477014	74
32	पश्चिम बंगाल	56809977	98
33	अभिसरण मंच	535040	10
34	प्रदर्शनी मंच	520920	8
35	सरस गैलरी	16370	8
कुल		357319223 **(₹ 35.73 करोड़)**	1835